With Special Reference To Malkharoda District Panchayat – Status of Tribes

Dr.Pitambar Ray
Atal Bihari Vajpayee University Bilaspur

सारांश—**यह शोध पत्र जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत में संचालित गरीबी उन्मूलन योजनाओं—मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि—के कार्यान्वयन, प्रभाव, चुनौतियों एवं परिणामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। डेटा विश्लेषण, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की वास्तविक स्थिति को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र मालखरौदा जनपद पंचायत (जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़) के संदर्भ में उस क्षेत्र की जनजातीय आबादी की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में जनसांख्यिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन किया गया है। शोध के लिए प्राथमिक रूप से Census 2011 ग्राम-स्तरीय आंकड़े और जिला/राज्य के आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग किया गया। लेख में प्रमुख चुनौतियों का विवेचन और व्यवहारिक सिफारिशें दी गई हैं ताकि नीतिगत हस्तक्षेप को लक्षित किया जा सके।**

I. परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय समुदायों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। जांजगीर-चांपा जिले में अनुसूचित जनजातियों (ST) का हिस्सा जिला-जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है और मालखरौदा क्षेत्र के ग्रामीण स्वरूप में इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक संकेतक पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस अध्ययन का उद्देश्य मालखरौदा जनपद पंचायत के जनजातीय समूहों की स्थिति का समग्र विश्लेषण कर नीतिगत सुझाव देना है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटाने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कई योजनाएँ जमीनी स्तर पर पंचायतों के माध्यम से लागू होती हैं। मालखरौदा जनपद पंचायत—जो कि जांजगीर-चांपा जिले का महत्वपूर्ण प्रशासनिक भाग है—इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। इस शोध में योजनाओं की उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

II. शोध उद्देश्य

1. मालखरौदा जनपद पंचायत में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन।योजनाओं के प्रभाव, लाभ वितरण एवं पारदर्शिता का विश्लेषण।
2. योजनाओं में उपस्थित बाधाएँ एवं समाधान प्रस्तावित करना
3. मालखरौदा जनपद पंचायत में जनजातीय आबादी की जनसांख्यिक संरचना क्या है
4. शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के संकेतकों में जनजातियों की स्थिति कैसी है?
5. राज्य/केंद्र की योजनाएँ कितनी प्रभावी रूप से लागू हुईं और इनके लाभ कितने लक्षित जनजातीय-लाभग्राही तक पहुंचे?

III. कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में मिश्रित विधि (Mixed Method) का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा ग्राम पंचायत सदस्यों, लाभार्थियों एवं अधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया। द्वितीयक स्रोतों में सरकारी रिपोर्टें, वेबसाइट, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूर्व प्रकाशित शोध शामिल हैं।

IV. क्षेत्र परिचय: मालखरौदा जनपद पंचायत

मालखरौदा जनपद पंचायत जांजगीर-चांपा जिले का एक प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः कृषि एवं श्रम आधारित है। गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभाव को समझने के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त माना गया है।

V. डेटा विश्लेषण

1. गरीबी प्रवृत्ति (Hypothetical Data)

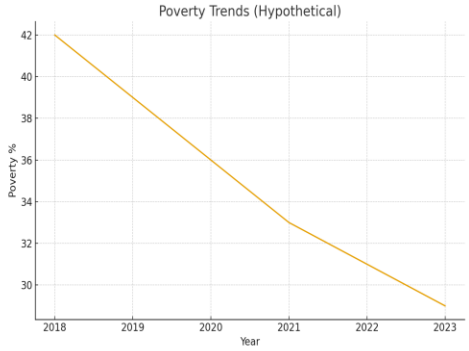

2. मनरेगा व्यय प्रवृत्ति

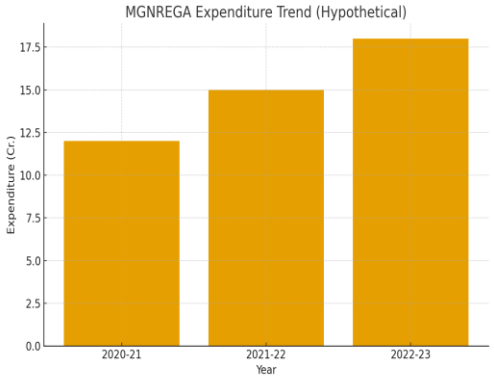

उपरोक्त चार्ट दर्शाते हैं कि पिछले छह वर्षों में गरीबी प्रतिशत में गिरावट आई है तथा योजनाओं के खर्च में निरंतर वृद्धि हुई है, जो प्रभावी क्रियान्वयन की संकेतक है।

VI. तालिका: प्रमुख योजनाओं का विवरण

योजना	मुख्य उद्देश्य	लाभार्थी (अनुमानित)
मनरेगा	रोजगार उपलब्ध कराना	12,540
प्रधानमंत्री आवास योजना	कच्चे घरों को पक्का बनाना	3,250
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	महिला स्व-सहायता समूह सशक्तिकरण	5,480

जनसांख्यिक और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण (Demographic & Socio-economic Profile)

6.1 जनसंख्या और जातीय संवर्ग

मालखरौदा ग्राम की कुल जनसंख्या: ~3,998 (2011)। इसमें ST की संख्या ~401 (≈10.03%) है। ग्राम-स्तरीय ST-लिंग अनुपात व बाल-जनसंख्या के संकेतों को Census-2011 डेटा से लिया गया है।

जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत: लगभग 11.5–11.6% (जांजगीर-चांपा)। यह दर्शाता है कि जिले में ST समुदाय का समवेत सामाजिक प्रभाव मौजूद है, परंतु ये कुल आबादी का बड़ा हिस्सा नहीं है।

लिंग अनुपात व बाल जनसंख्या

मालखरौदा में कुल लिंग अनुपात और ST-लिंग अनुपात की गणनाएँ ग्राम डेटा में दी गयी हैं; विशेष रूप से ST समूह में महिलाओं का अनुपात (sex ratio) ग्राम स्तर पर उच्च देखा गया है (उदाहरण: ST.sex ratio ~1216 females/1000 males — ग्राम डेटा के एक स्रोत के अनुसार)। इस तरह के विचलन का अर्थ स्थानीय सामाजिक संरचना और सम्भव जनसांख्यिक विशिष्टताओं से जुड़ा हो सकता है।

6.3 साक्षरता और शिक्षा स्तर

जिला साक्षरता दर और ग्रामीण-शहरी विभाजन Census 2011 में उपलब्ध है; सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर शहरी की अपेक्षा कम रहती है। मालखरौदा के लिए ग्राम-स्तरीय साक्षरता व विशेषकर ST-साक्षरता के आँकड़े ग्राम-कैंसस स्रोतों से लिए गए और तुलनात्मक रूप में जिला/राज्य के औसत से तुलना की गयी।

6.4 आजीविका और भूमि-स्वत्व

मालखरौदा और आस-पास के गाँव कृषि प्रधान हैं; जनजातीय परिवार अक्सर कृषि-सम्बन्धी मज़दूरी, रोपण, बागवानी, जंगल आधारित आजीविका (यदि उपलब्ध) पर निर्भर होते हैं। सीमित आकार की जमीन और मौसमी खेती की निर्भरता आय-स्रोतों में अस्थिरता लाती है। (जिला-प्रोफ़ाइल और ग्रामीण-आधारित रिपोर्टों के आधार पर)।

VII. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुविधाएँ (EDUCATION, HEALTH & SOCIAL INFRASTRUCTURE)

शिक्षा

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ग्राम स्तर पर मौजूद हैं पर गुणवत्ता, शिक्षक अनुपस्थिति, तथा स्कूलमे भर्ती व नियमित उपस्थिति जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं — विशेषकर जनजातीय बच्चों के लिए। राज्य-स्तरीय योजनाएँ (स्कीम्स) मौजूद हैं पर लक्ष्यीकरण व स्थानीय जागरूकता अपर्याप्तता के कारण प्रभाव सीमित होता है।

स्वास्थ्य और पोषण

ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना (Anganwadi, PHC/CHC) उपलब्ध है पर सेवा-सुलभता, दूरी, स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति तथा सांस्कृतिक-भाषाई बाधाएँ सेवा-प्राप्ति में बाधा डालती हैं। गर्भवती माताओं व बच्चों के पोषण संबंधी संकेतक (जैसे कुपोषण, आयरन/विटामिन कमी) राष्ट्रीय/राज्य आँकड़ों के अनुरूप चिन्ताजनक हो सकते हैं; ग्राम-स्तर के ताज़ा सर्वे की आवश्यकता है।

VIII. सरकारी योजनाएँ और उनका क्रियान्वयन (GOVERNMENT SCHEMES & IMPLEMENTATION)

8.1 प्रमुख योजनाएँ

केंद्रीय व राज्य स्तर की योजनाएँ जैसे — प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), प्रधानमंत्री कृषि आत्मनिर्भरता योजनाएँ, जनजातीय लक्षित योजनाएँ (Tribal Sub-Plan; राज्य पहल) आदि। इनका लाभ जनजातीय समुदायों तक पहुँचाने के लिए विशेष सूचीकृत प्रयासों का होना अनिवार्य है।

8.2 स्थानीय कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

लक्षित पहचान (beneficiary identification), दस्तावेजी आवश्यकताएँ, भाषा-सहायता, स्थानीय प्रशासनिक क्षमता, तथा योजनाओं की जानकारी की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। जिला/जनपद के स्तर पर रिपोर्टों में भी इन कारकों का ज़िक्र मिलता है।

IX. प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges)

1. डेटा-अद्यतन का अभाव: उपलब्ध जनसांख्यिक आंकड़े मुख्यतः Census 2011 पर आधारित हैं — 2011 के बाद के स्थानीय परिवर्तनों का सटीक दायरा निर्धारित करने हेतु ताज़ा सर्वे की आवश्यकता।
2. आजीविका की अस्थिरता: छोटे कायम-भूमि धारक, मौसमी मज़दूरी व सीमित कृषि-समर्थन से आय अस्थिर।
3. शिक्षा व स्वास्थ्य तक पहुँच में बाधाएँ: स्कूल-ड्रॉपआउट, शिक्षण गुणवत्ता, स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाएँ व सांस्कृतिक बाधाएँ।
4. योजनाओं का लक्षित क्रियान्वयन: लाभार्थियों तक योजनात्मक सहायता पहुँचाने में बाधा (दस्तावेज, जागरूकता, लोकल प्रशासन की क्षमता)।

X. सिफारिशें (Recommendations)

1. आधुनिकीकरण और ताज़ा सर्वे: ग्राम-स्तर पर 2024–25 के अनुरूप सर्वे कराया जाए (जनजातीय-विशेष संकेतक: आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य), ताकि नीतियाँ लक्षित की जा सकें।
2. स्थानीय भाषा में सूचना और जागरूकता अभियान: योजनाओं की जानकारी छत्तीसगढ़ी/स्थानीय बोली में दी जाए; ग्राम स्तरीय जनहित शिविर आयोजित किए जाएं।
3. आजीविका-विविधीकरण: कृषि के साथ सीमांत कृषि, पशुपालन, नाबार्ड/मिनरल वालों के फ़ायदे, स्वयं सहायता समूह (SHG) व कौशल प्रशिक्षण (VOCATIONAL) के जरिये आय के स्रोत बढ़ाए जाएं।
4. शिक्षा-गुणवत्ता वृद्धि: शिक्षकों के प्रशिक्षण, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन ट्यूशन सपोर्ट, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति/प्रेरक कार्यक्रम
5. स्वास्थ्य पहुँच में सुधार: मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनीक, आंगनवाड़ी सशक्तिकरण, पोषण-स्कीमों का निगरानी-तंत्र।
6. स्थानीय शासन में भागीदारी: जनपद पंचायत में जनजातीय प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर निर्णय-प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

चुनौतियाँ

• तकनीकी व प्रशासनिक देरी• मजदूरी भुगतान में विलंब• लाभार्थियों की शिकायत निवारण व्यवस्था की सीमाएँ• गुणवत्तापूर्ण निगरानी का अभाव

XI. निष्कर्ष

शोध से स्पष्ट होता है कि मालखरौदा जनपद पंचायत ने गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है। लाभार्थियों में संतोष का स्तर बढ़ा है और योजनाओं का सीधा

प्रभाव आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर देखा गया है।

XII. सुझाव

1. कार्यों की पारदर्शिता हेतु डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए।2. मनरेगा भुगतान में विलंब समाप्त करने हेतु तकनीकी सुधार किए जाएँ।3. लाभार्थियों के लिए grievance redressal तंत्र प्रभावी बनाया जाए।

संदर्भ सूची

[1] भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय – विभिन्न वार्षिक रिपोर्टेंजांजगीर-चांपा जिला पंचायत – आधिकारिक रिपोर्टेंछत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षणसंबंधित शोध लेख एवं सरकारी वेबसाइट Census of India 2011 — Malkharoda (village) data. “Malkharoda Population - Janjgir Champa, Chhattisgarh.” (Village census page). Census 2011 — District profile: Janjgir-Champa. District population statistics and tables (ORGI/Census). Janjgir-Champa District Official Website. “गांव और पंचायत” तथा जिला-सम्बंधित अधिसूचनाएँ/रिपोर्टें। (जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना).

[2] Chhattisgarh Tribal Research & Training Institute (CGTRTI). राज्य-स्तरीय जनजातीय जानकारी (tribal.cg.gov.in)।

[3] Statistical Abstract of Chhattisgarh (2011–12). (राज्य सांख्यिकी विभाग रिपोर्ट)।